PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 053
दि. 22.06.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तमिलनाडु की सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से भयावह हादसा, 10 मजदूरों की मौत, 60 से अधिक गंभीर रुप से प्रभावित

चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में रविवार सुबह एक सीफूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में हुए अमोनिया गैस रिसाव ने पूरे क्षेत्र को दहशत और शोक में डुबो दिया। इस दर्दनाक औद्योगिक हादसे में सात महिलाओं समेत कुल 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर और आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी और भय का माहौल फैल गया।

यह हादसा तिरुवल्लूर जिले के पेरियापालयम क्षेत्र में स्थित एक झींगा प्रसंस्करण इकाई में हुआ, जहां रविवार सुबह रोजमर्रा की तरह काम चल रहा था। श्रमिक अपने-अपने कार्य में लगे हुए थे, तभी अचानक फैक्ट्री के भीतर अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में यह जहरीली गैस पूरे परिसर में फैल गई, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों को सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी। कई मजदूर घुटन और जलन महसूस करते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी कि लोगों को संभलने या बाहर निकलने का पर्याप्त समय ही नहीं मिल सका। फैक्ट्री के अंदर अफरा-तफरी मच गई और श्रमिक जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन जहरीली गैस के प्रभाव ने कई लोगों को मौके पर ही बेहोश कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सबसे पहले सात महिला श्रमिकों की मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान तीन अन्य मजदूरों ने भी दम तोड़ दिया, जिससे कुल मृतकों की संख्या 10 हो गई।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गईं। जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिला कलेक्टर एस. कविता ने बताया कि 46 मरीजों को वेल्स अस्पताल और 21 मरीजों को वेंकटेश्वरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से नौ गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।

गैस रिसाव की इस घटना ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अमोनिया गैस, जो कि सामान्यतः रेफ्रिजरेशन और प्रसंस्करण इकाइयों में उपयोग की जाती है, किसी तकनीकी खराबी या रखरखाव में चूक के कारण रिसी हो सकती है। हालांकि, वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी गहन जांच की जाएगी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए अरक्कोनम स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम को तुरंत घटनास्थल पर रवाना किया गया। लगभग 30 सदस्यीय विशेष दल अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों, गैस डिटेक्शन सिस्टम और बचाव सामग्री के साथ मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने की कार्रवाई शुरू की। एनडीआरएफ टीम ने फैक्ट्री परिसर में गैस के प्रभाव को नियंत्रित करने और अन्य श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चलाया, जो देर रात तक जारी रहा।

इस हादसे ने पूरे तिरुवल्लूर जिले को झकझोर कर रख दिया है। अस्पतालों में घायलों के परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई है और हर कोई अपने प्रियजनों की स्थिति जानने के लिए बेचैन है। कई लोगों की हालत इतनी गंभीर बताई जा रही है कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर लगातार उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

तमिलनाडु सरकार ने इस हादसे में मारे गए प्रत्येक मजदूर के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही सभी घायलों के मुफ्त और समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। राज्य प्रशासन ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पीड़ित परिवार को इलाज या सहायता के लिए परेशान न होना पड़े।

राज्यपाल आर. एन. रवि ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और प्रशासन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश देने की बात कही है।

इस हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि रासायनिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियमित निरीक्षण की कमी इस तरह की घटनाओं का मुख्य कारण बनती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे हादसे दोबारा भी हो सकते हैं।

फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गैस रिसाव किस तकनीकी या मानवीय त्रुटि के कारण हुआ और क्या इसे समय रहते रोका जा सकता था। यह हादसा न केवल तमिलनाडु, बल्कि पूरे देश के लिए औद्योगिक सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आया है।

राम मंदिर दान प्रकरण पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- "कहीं एसआईटी की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए"

लखनऊ। अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावे की कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच अब राजनीतिक विवाद का बड़ा मुद्दा बन गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह जांच की गति और प्रक्रिया चल रही है, उसे देखते हुए यह भी आशंका जताई जा सकती है कि कहीं एसआईटी की रिपोर्ट ही "गायब" न हो जाए। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और सत्ता-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच के लिए बनी विशेष जांच टीम संभवतः और समय मांग सकती है, लेकिन सवाल यह है कि यह अतिरिक्त समय किस उद्देश्य से लिया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि कहीं यह देरी सबूतों को प्रभावित करने या मामले को कमजोर करने के लिए तो नहीं की जा रही है। उनके इस बयान ने पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग दे दिया है और यह मुद्दा अब केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित न रहकर सियासी बहस का केंद्र बन गया है।

गौरतलब है कि राम मंदिर परिसर में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। टीम ने कई दिनों तक अयोध्या में रहकर तथ्यों, रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच की है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जांच प्रक्रिया लगातार जारी है।

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर चुकी है, जो लगभग 140 पन्नों की बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में जांच के दौरान मिले तथ्यों, रिकॉर्ड और बयानबाजी का विस्तार से उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी अभी भी जुटाई जा रही है, जिसके चलते कुछ जांच अधिकारी राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहकर आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, जांच टीम ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से भी दोबारा पूछताछ की है। यह पूछताछ बंद कमरे में करीब तीन घंटे तक चली, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि जांच एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से देख रही हैं और हर पहलू को दस्तावेजी रूप से दर्ज किया जा रहा है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि यह रिपोर्ट सोमवार को लखनऊ में प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और यदि किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही साबित होती है तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

बताया जा रहा है कि यदि दान पेटियों के प्रबंधन में किसी प्रकार की गड़बड़ी या प्रक्रिया संबंधी लापरवाही सामने आती है, तो कुछ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं। इस पूरी जांच को लेकर सरकार स्तर पर भी गंभीरता दिखाई जा रही है और माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद बड़ा प्रशासनिक निर्णय संभव है। वहीं, विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि यदि मामला इतना गंभीर है तो प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई और जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित है तथा किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल यह मामला प्रशासनिक जांच से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक ओर जांच रिपोर्ट को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इसे अपने-अपने तरीके से मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एसआईटी रिपोर्ट और उस पर सरकार की कार्रवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।

नीतीश कुमार पर फिर जताया गया भरोसा चौथी बार बने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष

पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला किया है। राजधानी पटना स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को चौथी बार जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर औपचारिक मुहर लगा दी गई। इस निर्णय के साथ ही पार्टी ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि संगठन की कमान और रणनीतिक दिशा अब भी पूरी तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी।

बैठक के दौरान पूरे सभागार में उत्साह और समर्थन का माहौल देखने को मिला। जैसे ही नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी, वहीं उनके परिवार से जुड़े निशांत कुमार ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भावनात्मक हो गया।

राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केवल अध्यक्ष पद की पुष्टि ही नहीं की गई, बल्कि संगठनात्मक ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार को पार्टी संविधान में आवश्यक संशोधन करने सहित कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे उन्हें संगठनात्मक निर्णयों में और अधिक स्वतंत्रता मिल सकेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि पार्टी की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और संगठित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने राज्य में चल रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है और इसका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि बिहार अब विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक योजनाओं तक व्यापक सुधार देखने को मिल रहे हैं।

बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इनमें संगठन को मजबूत करने, सदस्यता विस्तार, विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और केंद्र-राज्य समन्वय को और बेहतर बनाने जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी की सदस्यता अब एक करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसे संगठन के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

राजीव रंजन सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में सत्ता का निरंतर और स्थिर नेतृत्व देश की राजनीति में एक अनूठा उदाहरण है। पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इसके बावजूद राज्य में व्यापक जन असंतोष का अभाव पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने दावा किया कि यह स्थिरता ही बिहार की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उमेश कुशवाहा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखा गया है, जिससे संगठनात्मक निरंतरता बनी रहेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि नेतृत्व में स्थिरता से संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी।

नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो वह पहले भी तीन बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें पहली बार 2016 में शरद यादव की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद 2019 में उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया और 2023 में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद तीसरी बार उन्होंने यह पद संभाला था। अब चौथी बार उनके नाम पर मुहर लगने के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी नेतृत्व उनके अनुभव और राजनीतिक कौशल पर पूरी तरह भरोसा करता है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार केवल एक नेता नहीं बल्कि जदयू की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक संतुलन की वजह से संगठन ने एक बार फिर उन्हें सर्वसम्मति से नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले के साथ जदयू ने आने वाले राजनीतिक समय के लिए अपनी रणनीतिक दिशा भी स्पष्ट कर दी है, जिसमें स्थिरता, विकास और संगठनात्मक मजबूती को प्राथमिकता दी जाएगी।

चीन के सहारे पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत, कितनी मजबूत और कितनी निर्भर?

कराची। पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति पिछले एक दशक में जिस तेजी से आधुनिक हो रही है, उसके केंद्र में चीन के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2015 में दोनों देशों के बीच हुए हैंगोर क्लास पनडुब्बियों के समझौते को इस सहयोग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उस समय इसे पाकिस्तान की नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया गया था, जिसका उद्देश्य केवल आधुनिक पनडुब्बियां हासिल करना नहीं बल्कि धीरे-धीरे तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना भी था। पाकिस्तान का दावा था कि यह साझेदारी उसे भविष्य में पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण की क्षमता तक पहुंचा देगी, लेकिन समय के साथ यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या यह लक्ष्य वास्तव में हासिल हो रहा है या फिर निर्भरता और बढ़ रही है।

इस परियोजना के तहत चार हैंगोर क्लास पनडुब्बियां पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में निर्मित की जा रही हैं, जबकि शेष चीन में तैयार हो रही हैं। यह व्यवस्था पाकिस्तान के लिए तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय निर्माण क्षमता बढ़ाने का अवसर मानी जा रही है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी विदेशी प्लेटफॉर्म को असेंबल करना और उससे वास्तविक डिजाइन क्षमता हासिल करना दो अलग-अलग स्तर की तकनीकी उपलब्धियां हैं। असेंबली लाइन पर काम करना अनुभव तो देता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नई पनडुब्बी डिजाइन करने की क्षमता विकसित करने के लिए गहरी वैज्ञानिक और औद्योगिक समझ की आवश्यकता होती है।

पाकिस्तान ने इससे पहले फ्रांसीसी अगोस्ता और डैफने क्लास पनडुब्बियों के संचालन और रखरखाव का अनुभव प्राप्त किया था। लेकिन हैंगोर क्लास पनडुब्बियां तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत हैं। लगभग 2,800 टन विस्थापन वाली ये पनडुब्बियां आधुनिक सेंसर सिस्टम, उन्नत हथियार नियंत्रण प्रणाली और डिजिटल युद्ध प्रबंधन तकनीक से लैस बताई जाती हैं। यही जटिलता इस बात को और महत्वपूर्ण बना देती है कि पाकिस्तान को वास्तव में कितनी तकनीक हस्तांतरित हो रही है और कितनी चीन के नियंत्रण में बनी हुई है।

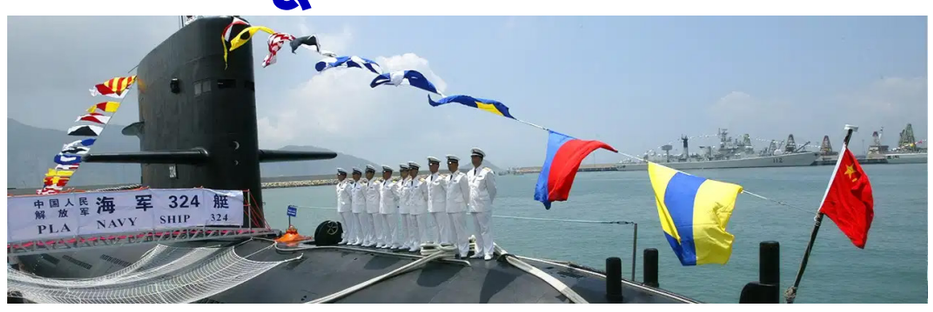

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आधुनिक पनडुब्बी की असली ताकत उसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम में होती है, जिसमें सेंसर, सोनार, फायर कंट्रोल और टारगेट ट्रैकिंग जैसी अत्यंत संवेदनशील तकनीक शामिल होती है। आमतौर पर इस तरह की तकनीक किसी भी देश द्वारा पूरी तरह साझा नहीं की जाती। ऐसे में यदि चीन ने भी सीमित तकनीक हस्तांतरण की नीति अपनाई है, तो पाकिस्तान भविष्य में इन प्रणालियों को स्वतंत्र रूप से अपग्रेड या संशोधित करने में सीमित हो सकता है।

इसके अलावा, पनडुब्बी कार्यक्रम केवल निर्माण तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका असली खर्च दशकों तक चलने वाले रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण में होता है। हैंगोर क्लास के अधिकांश महत्वपूर्ण घटक जैसे इंजन, सेंसर, हथियार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चीन से ही आते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि पाकिस्तान की परिचालन क्षमता लंबे समय तक चीनी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर रह सकती है। किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधा या राजनीतिक तनाव की स्थिति में यह निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी में बदल सकती है।

रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह स्थिति केवल नौसेना तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पूरे रक्षा ढांचे में चीन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पहले ही JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, टाइप 054A/P फ्रिगेट, आधुनिक रडार सिस्टम और मिसाइल तकनीक के लिए चीन पर निर्भर है। यह सहयोग पाकिस्तान को तत्काल सैन्य क्षमता तो देता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से उसकी स्वदेशी रक्षा अनुसंधान क्षमता को सीमित कर सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में एक स्वदेशी रक्षा उद्योग विकसित कर पा रहा है या फिर वह एक ऐसे मॉडल में फंसता जा रहा है जहां डिजाइन, तकनीक और स्पेयर पार्ट्स पर बाहरी देश का नियंत्रण बना रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तकनीक का मूल ज्ञान, सॉफ्टवेयर और सिस्टम इंटीग्रेशन का नियंत्रण किसी अन्य देश के पास रहता है, तो असली आत्मनिर्भरता हासिल करना बेहद कठिन हो जाता है।

पाकिस्तान की नौसेना का दीर्घकालिक लक्ष्य अपने स्तर पर पनडुब्बियां डिजाइन और विकसित करना है, लेकिन इसके लिए केवल विदेशी तकनीक का अनुभव पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए मजबूत औद्योगिक आधार, स्वतंत्र अनुसंधान क्षमता, उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और पूरी तरह स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य अभी भी काफी दूर माना जा रहा है।

इसी वजह से यह बहस लगातार जारी है कि चीन के साथ यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए रणनीतिक मजबूती का साधन है या फिर लंबे समय तक चलने वाली तकनीकी निर्भरता का रास्ता। हैंगोर परियोजना का वास्तविक मूल्यांकन इसी आधार पर होगा कि क्या यह पाकिस्तान को वास्तव में तकनीकी रूप से सक्षम बनाती है या उसे एक स्थायी सैन्य साझेदारी पर निर्भर बनाए रखती है।

संपादकीय

दवाओं की दुनिया में छिपा खतरा

स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है। नागरिकों का स्वस्थ रहना न केवल उनकी व्यक्तिगत खुशहाली के लिए आवश्यक है, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि बाजार में उपलब्ध हर दवा वैज्ञानिक परीक्षणों, गुणवत्ता मानकों और सुरक्षा की कठोर कसौटियों पर पूरी तरह खरी उतरे। लेकिन जब सरकार को वर्षों से बिक रही दवाओं पर अचानक प्रतिबंध लगाना पड़े और यह स्वीकार करना पड़े कि उनका कोई ठोस चिकित्सीय आधार नहीं था तथा उनका लगातार उपयोग लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तब यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर ऐसी दवाओं को बाजार में आने और लंबे समय तक बिकने की अनुमति कैसे मिल गई? हाल ही में केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी। ये ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें दो या उससे अधिक औषधियों को मिलाकर एक गोली, कैप्सूल या सीरप के रूप में तैयार किया जाता है। सिद्धांत रूप में ऐसी दवाओं का उद्देश्य रोगियों को सुविधा प्रदान करना और उपचार को अधिक प्रभावी बनाना होता है, लेकिन जब बिना पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के विभिन्न औषधियों को मिलाकर दवाएं बनाई जाती हैं, तब वे लाभ के बजाय नुकसान का कारण बन सकती हैं। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ने एक बार फिर देश की दवा नियामक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। सरकार का यह तर्क कि यह कदम जनस्वास्थ्य की रक्षा और दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन इससे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। यदि इन दवाओं का उपयोग वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं था, तो उन्हें पहले मंजूरी क्यों दी गई? यदि वे हानिकारक थीं, तो वर्षों तक उनके उत्पादन और बिक्री को क्यों जारी रहने दिया गया? स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह होना चाहिए कि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जाए, न कि उसके दुष्परिणाम सामने आने के बाद कार्रवाई की जाए। दुर्भाग्य से हमारे देश में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है कि नियामक संस्थाएं सक्रिय होने के बजाय तब जागती हैं जब समस्या गंभीर रूप ले चुकी होती है। और भी चिंता की बात यह है कि इन दवाओं की समीक्षा और जांच का काम भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुआ। यह स्थिति दर्शाती है कि जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन सरकार और नियामक संस्थाओं को स्वयं करना चाहिए, उनके लिए भी कई बार न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह किसी भी स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। दवाओं जैसी संवेदनशील वस्तु के मामले में तो यह और भी गंभीर विषय है, क्योंकि यहां सीधे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य का प्रश्न जुड़ा होता है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है। देश की दवा उद्योग वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और अनेक देशों को सस्ती तथा प्रभावी दवाएं उपलब्ध करा रहा है। लेकिन इसी के साथ यह भी सच है कि समय-समय पर घटिया, नकली और मानकों पर खरी न उतरने वाली दवाओं के मामले सामने आते रहते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी की जाने वाली गुणवत्ता जांच रिपोर्टों में अक्सर यह पाया जाता है कि अनेक दवाओं के नमूने परीक्षण में असफल हो गए। कई बार स्थिति इतनी गंभीर होती है कि संबंधित कंपनियों के लाइसेंस तक निलंबित करने पड़ते हैं। इसके बावजूद समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो पा रही है। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति कफ सीरप के क्षेत्र में देखने को मिली है। पिछले वर्षों में विषाक्त कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मृत्यु की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उन घटनाओं ने न केवल भारत की दवा निर्माण प्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। इसके बाद सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए और दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन समस्या की जड़ अब भी बनी हुई दिखाई देती है। केवल नियमों को कड़ा कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उत्पादन की हर प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी रखी जाए और गुणवत्ता मानकों का कठोरता से पालन कराया जाए।

युद्धों का चेहरा बदलता अदना-सा ड्रोन

> मौजूदा समय में ड्रोन युद्ध के तरीके को बदल रहे हैं। इसके चलते छोटे देश भी महाशक्तियों का मुकाबला कर पा रहे हैं। रूस-यूक्रेन और अमेरिका-इस्राइल-ईरान युद्धों में ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई। इसका असर जियो पॉलिटिक्स व सुरक्षा रणनीति पर होगा। भारत के लिए भी इससे सैन्य चुनौतियां पैदा हुई हैं।

तेरहवीं सदी में इंग्लिश लॉन्गबो (एक किस्म का लंबा धनुष) खतरनाक हथियार के तौर पर उभरा। इसको 13वीं और 15वीं सदी के बीच इंग्लैंड की सैन्य ताकत के दबदबे का प्रतीक माना जाता है। मध्ययुगीन युद्धों में लड़ाई की तकनीक में भी यह एक बड़ा बदलाव लेकर आया—इंग्लैंड की सैन्य ताकत कवच धारी कुलीनों से हटकर आम लोगों से बने तीरंदाजों की भुजाओं में आ गई। यह बदलाव इतना अहम था कि एडवर्ड तृतीय ने शाही फरमान जारी किया : '... प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति रविवार व छुट्टियों के दिन तीरंदाजी का अभ्यास करेगा, और अन्य सभी खेलों पर रोक होगी।'

एजिनकोर्ट की लड़ाई (सन 1415) शायद इस शक्ति परिवर्तन की बेहतरीन मिसाल है, जिसमें लगभग 7,000 सैनिकों की (इनमें 5,000 तीरंदाज थे) की छोटी सी इंग्लिश सेना ने कवच से लैस घुड़सवार योद्धाओं वाली विशाल फ्रांसीसी सेना (जिसमें करीब 20,000 सैनिक थे) को हरा दिया। लॉन्गबो ने आम लोगों को सैन्य ताकत का अहम हिस्सा बना दिया और व्यापार व कारीगरी की पूरी इकॉनोमी को आगे बढ़ाया।

शेक्सपियर ने अपने नाटकों में, एजिनकोर्ट की लड़ाई से पहले किंग हेनरी पंचम के संवादों से इस बदलाव को अमर बना दिया : 'हम कुछ लोग, चंद खुशकिस्मत लोग हैं, भाइयों से बना हमारा समूह है; जो कोई आज मेरे साथ अपना खून बहाएगा वह मेरा भाई होगा; चाहे वह कितने भी निम्न तबके से क्यों न हो, आज का दिन उसकी हैसियत ऊंचा उठाने वाला होगा।' वर्तमान में ड्रोन एक खतरनाक हथियार बन चुका है। यह आधुनिक युद्ध के तौर-तरीकों को बदल रहा है, जिसमें, कहीं छोटे देश भी महाशक्तियों की सैन्य ताकत का मुकाबला कर रहे और धूल चटा रहे हैं। यह होते हमने रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-इस्राइल-ईरान संघर्ष में देखा है।

गोलियथ (विशालकाय योद्धा) का मुकाबला डेविड इसलिए कर पाया कि उसने पास नए मारक हथियार के रूप में गुलेल थी, आज वही गुलेल ड्रोन का रूप

धर चुकी है। सस्ते और बड़े पैमाने पर बनने वाले ड्रोनों ने विशाल सेनाओं व जंगी बेड़ों का मुकाबला करने में कामयाबी हासिल की है।

आइए रूस का उदाहरण लें। रूस लंबे समय से यूक्रेन पर हमला करने और कब्जे में लेने की योजना बना रहा था। निरंतर अपना विस्तार कर रहे नाटो ने उसे ऐसा करने का बहाना दे दिया; नाटो ने यूक्रेन को सदस्य बनाकर, रूसी सीमाओं तक पहुंचकर उसके लिए खतरनाक बनना चाहा। रूसियों ने 'विशेष सैन्य अभियान' शुरू किया, जो कि दरअसल एक पूर्ण-स्तरीय हमला था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि कुछ ही दिनों में यह अभियान पूरा हो जाएगा। टीवी पर बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले यूक्रेन में घुसते देखे गए। हालांकि, उन्होंने दुश्मन को कमतर आंकने की बड़ी गलती की। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो का समर्थन मिला, खासकर हथियार, गोला-बारूद और खुफिया जानकारी के मामले में। धीरे-धीरे रूसी सेना मुश्किलों में फंसती गई। यूक्रेन ने शनैः-शनैः विशाल रूसी सेना की बढ़त रोक दी। 'द हिंदू' के हालिया लेख में कहा गया : 'यूक्रेन ने आम ड्रोन, जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, को तेजी से जासूसी और हमलावर प्रणाली में बदल दिया। जो फौरन निर्णायक युद्ध क्षमता में बदल गई, क्योंकि छोटे क्वाडकॉप्टर और फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को हथियारों से लैस कर कम लागत वाली किंतु सटीक निशाना लगाने वाली हथियार प्रणाली के तौर पर प्रयोग किया।' ड्रोन तबाही मचाने वाले सक्रिय हथियार बन गए और 2024 तक, यूक्रेनी सेना की लगभग हर टुकड़ी उससे लैस हो गई। तब से ड्रोन का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। ड्रोन ने युद्ध की दिशा-दशा बदल दी; बचाव की मुद्रा में रहने के बजाय, यूक्रेन अब रूस के गहरे अंदर तक हमले कर रहा। 'तीन दिन' का अभियान ऐसे युद्ध में बदल गया है, जो अब पांचवें साल में है।

इस संदर्भ में ईरान के साथ अमेरिका-इस्राइल युद्ध का ज़िक्र करना भी ज़रूरी है। अमेरिकियों ने खाड़ी क्षेत्र में विशाल सैन्य बेड़े भेजे, सैनिक जमा किए और अपनी ताकतवर वायु सेना को तैनात किया, साथ ही ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। इसके बाद, इस्राइल संग मिलकर हवाई हमले किए और ईरान के आध्यात्मिक, सैन्य और खुफिया नेतृत्व को खत्म कर दिया, और ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने तक की धमकी दी। अमेरिका ने ईरानियों की सभ्यतागत जीवट और इतिहास, तथा लाखों ड्रोन और मिसाइलों बनाने में उनकी तरक्की, उनके दूसरे एवं तीसरे स्तर के उनके नेतृत्व, और रणनीतिक व सामरिक सूझबूझ को अनदेखा किया—अहंकार और गलतियों ने फिर एक महाशक्ति को मात दे दी।

ईरानियों ने ड्रोन और मिसाइलों से खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी सहयोगियों के बुनियादी ढांचे पर हमले किए। इस्राइल पर भी ऐसे हथियारों से लगातार हमले किए। व्यापारिक जहाजरानी पर ड्रोन व मिसाइल हमलों के भय का इस्तेमाल कर होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद कर देना, रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक रहा; इसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। पुनः, एक प्रतिबद्ध सेना के हाथ में बड़ी संख्या में आम ड्रोनों ने क्षमता से कहीं ज़्यादा असर दिखाया और एक महाशक्ति व उसके सैन्य तंत्र को ठप कर डाला।

जैसे-जैसे ड्रोन से शक्ल पाकर 'अनघड़ लड़ाई' युद्धक्षेत्र का स्वरूप बदल रही है, इतिहास में इस किस्म की उथलपुथल से आगे चलकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते आए हैं। अंग्रेज़ों का 'लॉन्गबो' इसका उदाहरण था। इतिहास में ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे-जैसे सत्ता का संतुलन बदलता है और पुरानी व्यवस्था टूटती है, नए साम्राज्य और गठबंधन बनते हैं। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन 'बदलाव' की प्रक्रिया अपरिहार्य है।

सवाल है कि इन सबका भारत पर क्या असर पड़ेगा। मैंने अपने पिछले लेखों में चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश गठजोड़ के बारे में जिक्र किया है। जैसे-जैसे अमेरिका और चीन पर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे-वैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी (इस बाबत उसने जम्मू-कश्मीर को लेकर कई बार खुलकर कहा)। अमेरिका और रूस की गलतियों का फायदा चीन को ही होगा और वह उत्तर-पूर्व और लद्दाख में इलाकाई विवाद के अलावा भारत के साथ व्यापार के मामले में भी आक्रामक रुख अपनाए है। 21वीं सदी में जो एआई, रोबोट, ड्रोन और उर्जा उपयोग परिवर्तन का युग है- सैन्य और आर्थिक नए गठबंधन बनेंगे। अमेरिका पहले ही पुरानी मुक्त-व्यापार व्यवस्था भंग कर नए बदलाव लागू कर रहा है। चीन व उसकी औद्योगिक-व्यापारिक ताकत ने ही बदलाव करने को मजबूर किया। 18वीं और 19वीं सदी में, 'बड़ी ताकतों' में दुनिया को अपना उपनिवेश बनाने और उनके संसाधन उड़ाने की होड़ थी। आज, एक बार फिर सत्ता का पहिया घूम रहा है क्योंकि बड़ी ताकतें नियंत्रण और दबदबे के लिए होड़ कर रही हैं। इस उथल-पुथल भरे दौर में भारत को फौरन अपनी दिशा खोजनी होगी। बेरोजगारों की बढ़ती संख्या से हमारी अर्थव्यवस्था 'मध्य आय जाल' में फंसती जा रही है। स्नातक शिक्षित अधिकांश युवाओं की तन्खवाह इतनी नहीं जो आयकर योग्य सीमा में आ सके और उन्हें महंगाई से जूझना पड़ रहा है। महंगाई संग बेरोज़गारी , एक खतरनाक मिश्रण है, जिसका इस्तेमाल हमारे हितों के खिलाफ काम करने वाले तत्व अशांति फैलाने को कर सकते हैं। एफवीपी ड्रोन ने दिखाया है कि एकल ऑपरेटर द्वारा चालित यह उपकरण कितना नुकसान पहुंचा सकता है।

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर-पूर्व में लगातार ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल हथियार, गोला-बारूद और ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा है। उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर आदि में जारी तनावपूर्ण मुद्दों को सबको साथ लेकर चलने की भावना के साथ सुलझाना चाहिए। एकजुट होकर, देश को रणनीतिक साझेदारी और कूटनीति के ज़रिए अपने गठबंधनों को मज़बूत करने चाहिये।

रूस और अमेरिका के अनुभवों को देखते हुए, भारत को अपनी लघु और दीर्घ कालीन सैन्य रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और नए हथियार प्रणाली खरीदने के अलावा नूतन प्रतिकार उपाय अपनाने की ज़रूरत है।

प्रेरणा

जब प्रशंसा अंधा बना दे

मनुष्य के जीवन में प्रशंसा का अपना महत्व है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अच्छे कार्यों की सराहना हो, उसके प्रयासों को सम्मान मिले और उसकी उपलब्धियों को स्वीकार किया जाए। उचित प्रशंसा व्यक्ति को प्रेरणा देती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। किंतु जब यही प्रशंसा सीमा लांघकर चापलूसी का रूप धारण कर लेती है, तब वह प्रेरणा का साधन नहीं रहती, बल्कि पतन का कारण बन जाती है। संसार में अनेक लोग शत्रुओं के कारण नहीं, बल्कि चापलूसों के कारण बर्बाद हुए हैं। शत्रु सामने से हमला करता है, इसलिए उससे बचाव संभव होता है, लेकिन चापलूस मुस्कुराते हुए व्यक्ति की विवेक शक्ति को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि प्राचीन विद्वानों ने चापलूसी को मीठा जहर कहा है। एक बार एक राजा अपने राजदरबार में बैठे हुए थे। उनके आसपास राज्य के श्रेष्ठ विद्वान, मंत्री और राजपुरोहित उपस्थित थे। चर्चा ज्ञान और नीति से संबंधित विषयों पर चल रही थी। तभी राजा के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, "संसार में सबसे जहरीला प्राणी कौन है?" प्रश्न सुनते ही दरबार में विचारों की बौछार शुरू हो गई। किसी ने कहा कि सांप सबसे विषैला होता है। दूसरे ने बिच्छू का नाम लिया। किसी ने ततैया और किसी ने मधुमक्खी को सबसे खतरनाक बताया। सभी अपने-अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। अंत में उन्होंने राजगुरु की ओर देखा और कहा, "गुरुदेव, आप बताइए कि आपकी दृष्टि में सबसे जहरीला कौन है?" राजगुरु मुस्कुराए और बोले, "राजन, मेरी दृष्टि में संसार के सबसे जहरीले दो प्राणी हैं—निंदक और चाटुकार।" राजा को यह उत्तर आश्चर्यजनक लगा। उन्होंने पूछा, "गुरुदेव, ये तो मनुष्य हैं। इन्हें सांप या बिच्छू से अधिक विषैला कैसे कहा जा सकता है?" राजगुरु ने उत्तर दिया, "सांप और बिच्छू का विष केवल शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन निंदक और चाटुकार का विष मनुष्य की बुद्धि और आत्मा को प्रभावित करता है। निंदक अपने शब्दों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है, जबकि चाटुकार उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। निंदक का विष कड़वा होता है, इसलिए उसे पहचानना आसान होता है। लेकिन चाटुकार का विष मीठा होता है, इसलिए वह अधिक खतरनाक होता है।" यह उत्तर केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। संसार में निंदक से बचना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि उसका विरोध और आलोचना स्पष्ट दिखाई देती है। वह व्यक्ति की कमियां ढूंढ़ता है और उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। लेकिन चाटुकार उससे कहीं अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह व्यक्ति के दोषों को गुण बताता है। वह उसकी हर बात की प्रशंसा करता है, चाहे वह सही हो या गलत। धीरे-धीरे व्यक्ति उसकी बातों पर विश्वास करने लगता है और उसे लगने लगता है कि वह त्रुटिहीन है। यहीं से पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को देखना बंद कर देता है, तब उसके विकास की संभावना भी समाप्त होने लगती है। आत्मसुधार का आधार आत्मनिरीक्षण है, और आत्मनिरीक्षण तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे। चापलूसी व्यक्ति को यह अवसर नहीं देती। वह उसे एक ऐसे भ्रम में डाल देती है जिसमें उसे केवल अपनी महानता दिखाई देती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब शक्तिशाली राजा, सेनापति और शासक चापलूसों के कारण विनाश की ओर बढ़ गए। उनके आसपास ऐसे लोग एकत्र हो गए जो केवल उनकी प्रशंसा करते थे। कोई भी उनकी गलतियों की ओर संकेत करने का साहस नहीं करता था। परिणामस्वरूप वे वास्तविक परिस्थितियों से अनजान रहे और ऐसे निर्णय लेते गए जिन्होंने उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दूसरी ओर वे शासक अधिक सफल हुए जिन्होंने अपने आसपास सत्य बोलने वाले लोगों को स्थान दिया। उन्हें आलोचना सुनने में भले ही असुविधा होती हो, लेकिन वही आलोचना उन्हें सही दिशा देती थी। आज के युग में भी यह समस्या उतनी ही प्रासंगिक है। राजनीति, व्यापार, प्रशासन, शिक्षा और यहां तक कि पारिवारिक जीवन में भी चापलूसी का प्रभाव देखा जा सकता है। अनेक लोग योग्यता से अधिक महत्व प्रशंसा को देने लगते हैं। उन्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं जो हर समय उनकी तारीफ करें और उनकी बातों का समर्थन करें। धीरे-धीरे वे सत्य सुनने की क्षमता खो देते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाती है।

सोशल मीडिया के दौर में तो चापलूसी ने एक नया रूप ले लिया है। आज लोग लाइक, फॉलोअर्स और प्रशंसात्मक टिप्पणियों के माध्यम से आत्मसंतोष प्राप्त करने लगे हैं। लोकप्रियता को सफलता का पर्याय मान लिया गया है। ऐसे वातावरण में व्यक्ति के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि कौन उसकी वास्तविक प्रशंसा कर रहा है और कौन केवल स्वार्थवश उसकी चापलूसी कर रहा है। कई बार व्यक्ति इस भ्रम में जीने लगता है कि वह जितना महान स्वयं को समझ रहा है, वास्तव में उतना है नहीं। चापलूसी का एक और गंभीर दुष्परिणाम यह है कि यह संस्थाओं को भी कमजोर कर देती है। जब किसी संगठन में सत्य बोलने के बजाय केवल वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने की संस्कृति विकसित हो जाती है, तब निर्णयों की गुणवत्ता गिरने लगती है। लोग समस्याओं को छिपाने लगते हैं और वास्तविक चुनौतियां अनदेखी रह जाती हैं। परिणामस्वरूप संस्था धीरे-धीरे अपनी प्रभावशीलता खो देती है। महान संत कबीर ने कहा था कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी कमियों को उजागर करता है। इस कथन का अर्थ यह नहीं कि निंदा अच्छी है, बल्कि यह कि आलोचना हमें आत्ममंथन का अवसर देती है। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनना चाहता है, वह स्वयं को सुधारने का अवसर खो देता है। आलोचना यदि सद्भावना से की जाए तो वह विकास का माध्यम बन सकती है, जबकि चापलूसी विकास की प्रक्रिया को रोक देती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रशंसा और आलोचना दोनों को संतुलित दृष्टि से देखे। प्रशंसा से प्रेरणा ले, लेकिन उससे अहंकार पैदा न होने दे। आलोचना से सीख ले, लेकिन उससे निराश न हो। जो व्यक्ति इस संतुलन को बनाए रखता है, वही निरंतर प्रगति करता है। उसे न तो चापलूसी भ्रमित कर पाती है और न ही आलोचना कमजोर बना पाती है। वास्तविक मित्र वह नहीं होता जो हर समय हमारी तारीफ करे। सच्चा मित्र वह होता है जो आवश्यकता पड़ने पर हमारी गलतियों की ओर भी संकेत करे। जो व्यक्ति हमें हमारी सीमाओं का बोध कराए, वही हमारा हितैषी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल हमारी प्रसन्नता के लिए झूठी प्रशंसा करता है, वह धीरे-धीरे हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है।

एक नाजुक समझौता

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति को इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ छेड़े गए एक अनावश्यक युद्ध के उपरांत उसके साथ अंतरिम समझौता करना ही पड़ा। फिलहाल यह समझौता नाजुक लगता है। लेबनान के समझौते का हिस्सा होने के बाद भी इजरायल ने गत दिवस जिस तरह उस पर हमला किया, उससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका और ईरान अगले 60 दिन आपसी बातचीत के जरिये अनसुलझे मुद्दों को सुलझा सकेंगे? इजरायल और अमेरिका के लिए यह चिंता की बात है कि ईरान हमास, हिजबुल्ला और हाउती जैसे उन संगठनों की मदद करता है, जो इजरायल के लिए खतरा बने हुए हैं। हालांकि ट्रंप लेबनान को लेकर इजरायल को संयमित रहने के लिए चेता रहे हैं, लेकिन क्या ईरान हिजबुल्ला पर लगाम लगाने की गारंटी लेने को तैयार है? यदि ईरान हिजबुल्ला पर लगाम नहीं लगाता तो इजरायल के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह लेबनान में उसे निशाना न बनाए।

अमेरिका-ईरान युद्ध में जो अबूझ पहेली है, वह यह कि आखिर ट्रंप को ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की जरूरत ही क्या थी? ईरान पिछले कई वर्षों से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था और माना जाता है कि वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। इससे इजरायल के साथ खाड़ी के देश भी चिंतित थे। ईरान के परमाणु हथियार बनाने के इरादे को देखते हुए अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे थे। इसके चलते ईरान के लिए अन्य देशों से व्यापार करना कठिन हो गया था। चूंकि अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, इसलिए कोई देश उसके प्रतिबंधों की अनदेखी कर ईरान से व्यापार करने का साहस नहीं जुटा पाता था। ईरान चीन के अलावा उन देशों को ही तेल बेच पा रहा था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वह अपना कुछ तेल चोरी-छिपे भी बेच रहा था। हालांकि उसकी अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही थी, लेकिन वह परमाणु हथियार बनाने के अपने इरादे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख था। आम धारणा है कि अमेरिका ने इजरायल के कहने पर ईरान पर हमला किया। ट्रंप इससे भी नाराज थे कि ईरान भारी दबाव के बाद भी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जुटा है। अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान को निशाना बनाते ही उसने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का निकलना बंद कर दिया। इसके अलावा उसने खाड़ी देशों के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। ईरान ने उनके यहां हमला कर यह संदेश दिया कि वे अमेरिकी सैन्य संरक्षण में सुरक्षित नहीं। ईरान के पास मिसाइलों के साथ सस्ते, किंतु घातक क्षमता वाले ड्रोन का जखीरा था। इसी कारण वह अमेरिका के हमलों का जवाब देता रहा। अरबों डालर खर्च कर ईरान पर हमले करने के बावजूद अमेरिका उसकी सैन्य क्षमता को कुंद नहीं कर सका। अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक समस्या यह भी आ गई थी कि ईरान के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के लिए उन्हें संसद से अनुमति लेनी पड़ती और वह उन्हें मिलनी बहुत कठिन थी। शायद इसी कारण वे समझौता करने के लिए बाध्य हुए। हालांकि इस समझौते को वे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन ऐसा ही दावा ईरान भी कर रहा है। यह ठीक है कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया है, लेकिन क्या इजरायल इस पर भरोसा कर सकता है? यह देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो अंतरिम समझौता हुआ, वह अंतिम समझौते में तब्दील हो पाता है या नहीं? अमेरिका इससे तो चिंतित है कि ईरान चोरी-छुपे परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी चोरी-छुपे परमाणु हथियार बनाए और अमेरिका ने उस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाए। उसने पाकिस्तान को इसके लिए भी दंडित नहीं किया कि वह तमाम आतंकी समूहों को पाल रहा है। चूंकि अमेरिका दोहरे रवैया का परिचय देने में माहिर है, इसलिए विश्व में उसकी छवि और प्रतिष्ठा गिरती चली जा रही है। एक समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस पाकिस्तान को धोखेबाज करार दिया था, उससे ही वे दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे यह अवसर प्रदान किया कि वह अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने की भूमिका निभाए। हालांकि इस समझौते में कुछ अन्य देशों की भी भूमिका है, लेकिन अमेरिका ने ईरान से समझौता करने के लिए जिस तरह पाकिस्तान का साथ लिया, उससे उसे अपने को शांति का समर्थक बताने का मौका मिल गया है, जबकि सब जानते हैं कि वह एक गैर-जिम्मेदार राष्ट्र है और उसकी ऐसी हैसियत भी नहीं कि वह अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा सके। हैरानी नहीं कि उसे महज संदेशों का आदान-प्रदान करने वाले देश के रूप में देखा गया।

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद होर्मुज समुद्री मार्ग खुल गया है और जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम नरम पड़े हैं। इसका सीधा लाभ भारत के साथ विश्व के तमाम देशों को मिलेगा। आशा की जाती है कि बीते लगभग सौ दिनों में तेल, गैस और उर्वरकों के दाम बढ़ने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उनका धीरे-धीरे समाधान होगा। यदि अमेरिका-ईरान के बीच समझौता कारगर साबित होता है तो इससे पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के साथ विश्व अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी, क्योंकि होर्मुज से विश्व के पांचवें हिस्से की ऊर्जा का निर्यात होता है। समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान पर जो तमाम प्रतिबंध लगा रखे थे, उन्हें हटा लिया है। इसके चलते अब भारत भी उससे तेल खरीदने में समर्थ हो जाएगा। वह ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह का विकास भी कर सकता है। ईरान से तेल आयात इसलिए लाभकारी है, क्योंकि वह रूस, अमेरिका और वेनेजुएला की तुलना में कुछ सस्ता पड़ेगा। समझौते के तहत अमेरिका इसके लिए भी तैयार हुआ कि वह ईरान के विकास के लिए 300 अरब डालर के एक कोष की स्थापना में मदद करेगा। इसकी अमेरिका में आलोचना हो रही है। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन कुल मिलाकर यह समझौता विश्व के लिए राहतकारी है।

अभियान

जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के घर आते हैं: जगन्नाथ रथ यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य

भारत की सनातन परंपराओं में अनेक पर्व और उत्सव ऐसे हैं जो केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण, समानता और आध्यात्मिक चेतना के जीवंत प्रतीक हैं। इन्हीं में से एक है ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की विश्वविख्यात रथ यात्रा। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भक्ति का महापर्व है। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आरंभ होने वाली यह यात्रा संसार के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के दिव्य रथों के दर्शन करते हैं। लेकिन इस यात्रा का सबसे आकर्षक और रहस्यमय पक्ष वह होता है जब लाखों भक्त भगवान के रथ की रस्सी को खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। यह दृश्य केवल धार्मिक उत्साह नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच अद्वितीय संबंध का प्रतीक है।

जगन्नाथ संस्कृति में भगवान को केवल मंदिरों की चारदीवारी में सीमित देवता नहीं माना गया है। यहां भगवान जगन्नाथ को "जन-जन के नाथ" कहा जाता है। उनका स्वरूप भी अन्य देवताओं से अलग है। वे ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों के बीच आना पसंद करते हैं। रथ यात्रा इसी भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्षभर श्रीमंदिर के गर्भगृह में विराजमान रहने वाले भगवान इस दिन अपने भक्तों के दर्शन के लिए बाहर निकलते हैं। यह मान्यता है कि जो भक्त किसी कारणवश मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हें भी भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा को "भगवान के घर से बाहर आने का उत्सव" भी कहा जाता है।

रथ की रस्सी खींचने का महत्व केवल एक धार्मिक क्रिया तक सीमित नहीं है। सनातन मान्यताओं के अनुसार भगवान के रथ को श्रद्धा और भक्ति से खींचने वाला व्यक्ति विशेष पुण्य का भागी बनता है। स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने में सहभागी होता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह भी माना जाता है कि रथ की रस्सी खींचना वास्तव में अपने जीवन रूपी रथ को भगवान की दिशा में अग्रसर करने का प्रतीक है। जब भक्त रथ की रस्सी पकड़ता है, तो वह केवल लकड़ी के बने विशाल रथ को नहीं खींच रहा होता, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, अज्ञान और मोह को भी पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहा होता है।

इस परंपरा का एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक संदेश भी है। सामान्यतः मनुष्य भगवान तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन रथ यात्रा में स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। यहां भगवान स्वयं अपने भक्तों तक आते हैं। यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में दूरी का कोई महत्व नहीं होता। भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं और उसके द्वार तक आने के लिए भी तैयार रहते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा को प्रेम, करुणा और ईश्वरीय अनुकंपा का उत्सव माना जाता है।

भगवान जगन्नाथ का रथ 'नंदीघोष' कहलाता है। यह अत्यंत भव्य और विशाल होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 विशाल पहिए लगे होते हैं। भगवान बलभद्र के रथ को 'तालध्वज' तथा देवी सुभद्रा के रथ को 'दर्पदलन' कहा जाता है। इन तीनों रथों का निर्माण हर वर्ष नई लकड़ियों से किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। विशेष बात यह है कि रथ निर्माण में आधुनिक तकनीक के बजाय पारंपरिक विधियों और शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता है। सैकड़ों कुशल कारीगर कई महीनों तक परिश्रम करके इन दिव्य रथों का निर्माण करते हैं। निर्माण कार्य को भी एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है और इसके प्रत्येक चरण में मंत्रोच्चार तथा पूजा-अर्चना की जाती है। जब रथ यात्रा आरंभ होती है तो सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ चलता है। उसके पीछे देवी सुभद्रा का रथ और अंत में भगवान जगन्नाथ का भव्य नंदीघोष रथ निकलता है। रंग-बिरंगे वस्त्रों, सुंदर चित्रकारी, आकर्षक झंडों और पुष्पों से सजे ये रथ देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जैसे ही रथ आगे बढ़ते हैं, चारों ओर "जय जगन्नाथ" के जयघोष गूंजने लगते हैं। लाखों श्रद्धालु हाथ जोड़कर भगवान का स्वागत करते हैं और रथ की रस्सी को स्पर्श करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं।

रथ यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू "छेरा पहरा" की परंपरा है। इस रस्म में पुरी के गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण झाड़ू लेकर भगवान के रथ के सामने मार्ग को साफ करते हैं। यह दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक होता है, क्योंकि इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान के सामने सभी समान हैं। चाहे कोई राजा हो या सामान्य व्यक्ति, ईश्वर के समक्ष सभी का स्थान एक समान है। यह परंपरा विनम्रता और सेवा भाव का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है।

रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई-बहन के साथ गुंडिचा मंदिर जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह उनकी मौसी का घर है। वहां भगवान लगभग नौ दिनों तक निवास करते हैं। इस अवधि में लाखों भक्त गुंडिचा मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद भगवान पुनः अपने मूल मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस वापसी यात्रा को "बहुदा यात्रा" कहा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार, प्रेम और आत्मीयता के भारतीय जीवन मूल्यों का भी प्रतीक है।

आध्यात्मिक दृष्टि से रथ यात्रा मानव जीवन का भी प्रतीक मानी जाती है। शरीर को रथ, आत्मा को यात्री और भगवान को मार्गदर्शक माना गया है। जब मनुष्य अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को सौंप देता है, तब उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। रथ की रस्सी खींचना इसी समर्पण का प्रतीक है। यह बताता है कि मनुष्य को अपने जीवन का केंद्र अहंकार नहीं, बल्कि ईश्वर को बनाना चाहिए।

जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशी भावना है। यहां जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और सामाजिक स्थिति का कोई भेदभाव नहीं होता। रथ की रस्सी खींचने के लिए सभी को समान अधिकार प्राप्त है। एक ही रस्सी को राजा भी पकड़ता है और सामान्य मजदूर भी। यही कारण है कि यह यात्रा सामाजिक समरसता और समानता का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ का अर्थ ही है "जगत के नाथ" अर्थात संपूर्ण विश्व के स्वामी। इसलिए उनकी कृपा भी सभी पर समान रूप से बरसती है।

सदियों से चली आ रही यह परंपरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव है। इसमें भक्ति है, दर्शन है, सामाजिक समरसता है, सेवा है और आध्यात्मिक संदेश भी है। जब लाखों लोग भगवान के रथ की रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, तब वे केवल एक रथ नहीं खींच रहे होते, बल्कि अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपने आध्यात्मिक जीवन को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं।

यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचने को अपना सौभाग्य मानते हैं। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि भगवान के साक्षात स्पर्श का अनुभव है। यह वह क्षण होता है जब भक्त और भगवान के बीच की सभी दूरियां समाप्त हो जाती हैं और केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण शेष रह जाता है। शायद यही वह रहस्य है जो जगन्नाथ रथ यात्रा को संसार के सबसे महान आध्यात्मिक उत्सवों में स्थान दिलाता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रोत्साहक उपस्थिति में गांधीनगर के माणसा में 12वें विश्व योग दिवस का राज्य स्तरीय उत्सव भव्य रूप से मनाया गया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- 12वें विश्व योग दिवस और प्रधानमंत्री के सुशासन के 12 वर्ष पूर्ण होने का शुभ समन्वय
- प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का महत्वपूर्ण माध्यम बना
- योग क्षेत्र में गुजरात देश में अग्रणी : 1.5 लाख प्रशिक्षक, पाँच हजार योग केन्द्रों के माध्यम से एक वर्ष में 8 लाख लोग योग से जुड़े
- राजकोट बनेगा देश की अनूठी '15 मिनट योग सिटी'

योग को राष्ट्र निर्माण की शक्ति बनाकर 'विकसित गुजरात से विकसित भारत@2047' के संकल्प को साकार करें : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

योग को केवल एक दिवस के कार्यक्रम तक सीमित न रखकर दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने का मुख्यमंत्री का आह्वान

समग्र राज्य में एक साथ 330 स्थानों पर सवा करोड़ से अधिक बच्चों, युवाओं तथा बड़े-बुजुर्गों ने योगाभ्यास किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रोत्साहक उपस्थिति में गांधीनगर के माणसा में रविवार को 12वें विश्व योग दिवस का राज्य स्तरीय उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहकर हमारी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनना चाहिए।

इसके साथ ही पूरे राज्य में एक साथ लगभग सवा करोड़ से अधिक बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने विभिन्न स्थानों से इस उत्सव में जुड़कर योगाभ्यास किया।

राज्य के सभी नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से हमारी सनातन प्राचीन योग संस्कृति को आज विश्वभर में स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि 12वें विश्व योग दिवस का उत्सव इस दृष्टि से भी विशेष है कि प्रधानमंत्री के सुशासन के भी 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 'फिट इंडिया' तथा 'विश्व योग दिवस' जैसी बड़ी भेंट दी है, जिसके परिणामस्वरूप योग आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इसके साथ ही पर्यावरण

संरक्षण के लिए 'एक पेड़ माँ के नाम', 'कैच द रेन' तथा सोलर एनर्जी द्वारा ग्रीन-क्लीन ऊर्जा का दृष्टिकोण और रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती तथा 'मिशन लाइफ' द्वारा पर्यावरण के साथ संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी प्रधानमंत्री ने दिखाया है।

मुख्यमंत्री ने बलपूर्वक कहा कि आज के तनावपूर्ण जीवन में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसे गंभीर रोगों के विरुद्ध योग स्वास्थ्यप्रद जीवन का सबसे सरल एवं सटीक मार्ग है।

श्री पटेल ने कहा कि इस वर्ष की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' है। 12वें विश्व योग दिवस पर समग्र गुजरात में विभिन्न स्थानों पर 330 से अधिक स्थानों पर सवा करोड़ से भी अधिक लोग सामूहिक योग में जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने गौरवपूर्वक कहा कि गुजरात योग क्षेत्र में सदैव अग्रसर रहा है। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा 1.5 लाख योग प्रशिक्षक तैयार कर देश में सर्वाधिक प्रशिक्षक तैयार करने की उपलब्धि प्राप्त की गई है। राज्य में 5000 से अधिक निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से एक वर्ष में 8 लाख से अधिक लोगों को योग से जोड़ा गया है।

इतना ही नहीं; राजकोट महानगर पालिका ने योग बोर्ड के साथ विशेष एमओयू कर '15 मिनट योग सिटी' का नूतन दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें शहर के किसी भी स्थान से 15 मिनट की दूरी पर योग केन्द्र उपलब्ध हो; ऐसी व्यवस्था करने का आयोजन है।

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ योग को राष्ट्र निर्माण की शक्ति बनाकर सभी लोग 'विकसित गुजरात से विकसित भारत@2047' के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के कार्य में जुड़ जाएँ।

राज्य योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री शीशपाल राजपूत ने सभी का स्वागत करते हुए दैनिक जीवन में योग का महत्व समझाया। उन्होंने योग को सनातन ऋषि परंपरा की अद्वितीय भेंट बताते हुए 365 दिनों तक योग को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कॉमन योग प्रोटोकॉल के साथ सभी को योगाभ्यास भी कराया।

इस अवसर पर सभी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।

इस कार्यक्रम में गांधीनगर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश पटेल, विधायक श्री जयंतीभाई पटेल व श्री प्रकाशभाई वरमोरा, माणसा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सनाबेन वाघेला, तहसील पंचायत अध्यक्ष श्री भरतसिंह राठौड़, सर्वोदय एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. वी. एन. शाह, जिला कलेक्टर श्री रवीन्द्र खताले तथा जिला विकास अधिकारी सुश्री हसरत जैस्मीन सहित बड़ी संख्या में योग कोच, योग प्रशिक्षक और योगकर्मी उपस्थित रहे।

गांधीनगर में आगामी 23 जून को 'गुजरात टू ग्लोबल : एम्पावरिंग द मेडटेक इकोसिस्टम' परिषद का किया जाएगा आयोजन

मेडटेक क्षेत्र में गुजरात की वैश्विक उड़ान को गति देगी यह ग्रिट तथा ईपीसीएमडी इंडिया परिषद

गांधीनगर : गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस (ईपीसीएमडी इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से 'गुजरात टू ग्लोबल : एम्पावरिंग द मेडटेक इकोसिस्टम' शीर्षक अंतर्गत मेडटेक क्षेत्र की एक उच्चस्तरीय परिषद का आयोजन आगामी 23 जून, 2026, मंगलवार को गांधीनगर में किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन क्षमताओं एवं वैश्विक बाजारों में प्रवेश के बीच अंतर को दूर करना है। इसके लिए नीति निर्माताओं, नियमनकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा उद्योग जगत के अग्रणियों को एक ही मंच पर लाया जाएगा।

यह कार्यक्रम गुजरात के मेडिकल डिवाइस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में आयोजित हो रहा है। राजकोट के निकट स्थित नागलपर मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्यरत होने से राज्य के उत्पादक अब मूलभूत असेंबली से आगे बढ़कर उच्च गुणवत्ता वाले तथा निर्यातोन्मुख उत्पादों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इस समग्र कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रिट की सीईओ श्रीमती एस. अपर्णा द्वारा की जाएगी। भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग तथा वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त; उद्योग एवं सरकार के दो दर्जन से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न सत्रों में सक्रिय भाग लेंगे।

दिनभर की चर्चाओं की शुरुआत नीति एवं उद्योग संबंधी मुद्दों पर आधारित सत्र से होगी। इसमें '2030 रोडमैप : देश के 30 अरब डॉलर के मेडटेक विजन में गुजरात की भूमिका' संबंधी प्रस्तुति द्वारा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद गुजरात के उत्पादकों के दृष्टिकोण से नीति, नियमनकारी ढाँचे और बाजार तक पहुँच से संबंधित चुनौतियों पर संवाद-चर्चा आयोजित होगी। फार्मास्युटिकल्स विभाग, वाणिज्य विभाग और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अलावा; एसएमटी, बीपीएल, मेरिल लाइफ साइंस और फिलिप्स इंडिया जैसी अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे।

यहाँ विशेष तकनीकी सत्र में वैश्विक नियमनकारी मंजूरियों के लिए निर्णायक ढाँचा प्रस्तुत किया जाएगा; जिसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के विभिन्न मार्गों (510(k), De Novo, PMA) तथा EU MDR और IVDR की आवश्यकताओं के साथ उनकी सुसंगतता पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में सीडीएससीओ, एफडीए के थर्ड-पार्टी समीक्षा संस्थानों और यूरोपीय नोटिफाइड बॉडीज के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे।

इसके बाद के सत्र में वैश्विक बाजारों में प्रवेश के लिए निर्यातोन्मुख गुणवत्ता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इसमें जीरो इफेक्ट-जीरो डिफेक्ट (ZED) मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों के साथ जोड़ने तथा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है; इस विषय पर चर्चा होगी। इस सत्र में Invest India, ADMI, Panacea Medical Technologies तथा Wipro GE Healthcare सहित विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

अंतिम सत्र गुजरात के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए सहायक इकोसिस्टम के विकास पर केन्द्रित रहेगा। इसमें आधारभूत सुविधाएँ, नियमनकारी सहायता, अनुसंधान एवं नवाचार, आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण, कौशल विकास तथा उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि ग्रिट राज्य का सर्वोच्च नीति विचार मंच है, जो शासन सुधार एवं विकासोन्मुख रणनीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जबकि ईपीसीएमडी इंडिया भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग के अधीन कार्यरत संस्थान है, जिसे भारतीय मेडिकल डिवाइसेस के वैश्विक स्तर पर निर्यात संवर्धन की जिम्मेदारी निभानी होती है।

पश्चिम रेलवे पर उत्साहपूर्वक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,स्वस्थ आयु के लिए योग : समग्र स्वास्थ्य एवं सक्रिय जीवनशैली के महत्व पर दिया गया विशेष जोर

पश्चिम रेलवे पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रविवार, 21 जून, 2026 को पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" रखी गई थी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण से हुई, जिसके पश्चात राष्ट्रव्यापी कॉमन योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके उपरांत पश्चिम रेलवे मुख्यालय में एक योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पाण्डेय, प्रमुख विभागाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों, मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा रेल कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

"स्वस्थ आयु के लिए योग" विषय जीवनभर शारीरिक गतिशीलता, मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र स्फूर्ति को बढ़ावा देने में योग के महत्व को रेखांकित करता है। नियमित शारीरिक गतिविधि, माइंडफुल ब्रीदिंग तथा आंतरिक संतुलन पर बल देने के माध्यम से योग स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। योग को जीवनशैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित कर पश्चिम रेलवे अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के बीच समग्र स्वास्थ्य तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल को निरंतर बढ़ावा दे रही है।

प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान अभ्यासों का प्रदर्शन किया तथा शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता एवं समग्र स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त किया।

पश्चिम रेलवे के सभी छह मंडलों, कारखानों, प्रशिक्षण संस्थानों, डिपो, शेडों तथा अन्य रेल प्रतिष्ठानों में भी योग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में पूरे क्षेत्र में उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली, जो योग के लाभों तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे ने लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु अपने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से जागरूकता संदेश एवं डिजिटल क्रिएटिव भी प्रसारित किए। इन पहलों के माध्यम से पश्चिम रेलवे ने अपने कर्मचारियों एवं यात्रियों के बीच स्वास्थ्य, कल्याण एवं संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।

हाल में जेल केवल सजा भुगतने का स्थान नहीं, बल्कि एक 'प्रायश्चित भवन' और सुधार गृह है : जेल प्रभाग के राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल

गुजरात की जेल व्यवस्था को मिलेगी नई शक्ति : जेल प्रभाग के राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल के करकमलों से गांधीनगर से वर्ग-1 तथा 2 के कुल 11 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए

गांधीनगर : जेल प्रभाग के राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल ने कहा है कि वर्तमान समय में जेल केवल सजा भुगतने का स्थान नहीं है, बल्कि एक 'प्रायश्चित भवन' और सुधार गृह बन चुकी है। जब हम पूरी ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तब ईश्वर हमारे परिवार की भी चिंता करता है।

श्री पटेल ने गृह विभाग के जेल प्रभाग के अंतर्गत नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले वर्ग-1 और वर्ग-2 के कुल 11 अधिकारियों को रविवार को गांधीनगर स्थित स्वर्णिम संकुल में नियुक्ति पत्र प्रदान समारोह में यह बात कही। कार्यक्रम में श्री पटेल तथा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के करकमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर श्री पटेल ने भगवान श्री कृष्ण के 'कर्मयोग के सिद्धांत' को स्मरण करते हुए नियुक्ति प्राप्त करने वाले अधिकारियों को निष्ठापूर्वक एवं उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जेल में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात

अपराधी या आपराधिक मानसिकता वाला नहीं होता। कई बार अपराधी परिस्थितिवश भी अपराध की ओर चले जाते हैं। इसलिए हमें मानवता तथा निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सरकार पर्याप्त आयोजना कर रही है, लेकिन जेल में आने वाले कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहना भी बहुत अनिवार्य है। कैदियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले जेल अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वयं मानसिक रूप से पावरफुल और मजबूत बनना होगा। साबरमती जेल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ कैदियों द्वारा बढ़ई कार्य, फर्नीचर निर्माण और फूड पैकिंग जैसे अनेक छोटे-बड़े उद्योग सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण से कैदी जेल से बाहर जाकर भी आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त; जेल में रहने वाली महिलाओं और यदि उनके साथ कोई मासूम बच्चा हो, तो उनके प्रति विशेष मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जेल प्रशासन को अधिक सशक्त, आधुनिक और कार्यक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोड़ा कि नई नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों के जुड़ने से जेल प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और सुधारात्मक सेवाओं को अधिक गति मिलेगी।

राज्य मंत्री ने कहा कि गुजरात में जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो, वहाँ जेल सुधार के ऐसे श्रेष्ठ कार्य करें कि पूरे देश में गुजरात की जेलों और हमारे विभाग का संज्ञान लिए जाने के साथ गौरव बढ़े।

इस अवसर पर प्रधान सचिव (गृह) श्रीमती निपुणा तोरवणे, गृह विभाग एवं जेल प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा नई नियुक्ति प्राप्त अधिकारी उपस्थित रहे।

नियुक्ति प्राप्त अधिकारी

अधीक्षक, केन्द्रीय जेल / पोरबंदर विशेष जेल, वर्ग-1

1.श्री अतुलकुमार छगनभाई मकवाणा
2.सुश्री डिम्पल अर्जुनभाई पटेल
3.श्री गौतमकुमार हरेशभाई व्यास
4.श्री सौरभकुमार लक्ष्मणभाई राठौड़
5.श्री शैलेषकुमार रमणलाल सागर

जेलर ग्रुप-1 (पुरुष), वर्ग-2

1.श्री परेशभाई वशरामभाई डांगर
2.श्री अनीश हसन सुमरा
3.श्री डाह्याभाई मोडाभाई डीघारी
4.श्री सागरकुमार ओघडभाई कलसरिया
5.श्री आर्यन करशनभाई पटेल
6.श्री मेहुलभाई चीकाभाई धरजिया

वडोदरा मंडल पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्साह पूर्वक आयोजन

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर 12वाँ "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" उत्साहपूर्वक मनाया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वडोदरा मंडल पर "स्वस्थ आयु के लिए योग (Yoga for Healthy Ageing)" की थीम पर योग सत्र का आयोजन किया गया । प्रतापनगर स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में प्रातः 6:00 बजे से 7:50 बजे तक योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वंदे मातरम् के साथ हुआ।

वडोदरा शहर की जानीमानी योग गुरु श्रीमती कृष्णा पटेल एवं कुमारी ख़ुशी पटेल तथा उनकी टीम के मार्गदर्शन में रेल अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान संबंधी सुन्दर योगाभ्यास किया।

इस अवसर पर वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने अपने संबोधन में कहा कि योग हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की इस अनमोल प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को हमें अपने दैनिक जीवन में उतारना जरूरी है । योग हमें स्ट्रेस और नेगेटिविटी से क्रियेटिविटी व तनावमुक्त जीवन की ओर ले जाता है और जीवन में नई संभावनाएं व ऊर्जा उत्पन्न करता है। "योग को न केवल रेल कर्मचारियों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए अपितु अपने परिजनों को भी इस हेतु प्रेरित करना चाहिए ताकि सभी लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें"।

सामूहिक योग अभ्यास के इस कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा मंडल की अध्यक्षा डॉ कविता भडके, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संगठन की अन्य सदस्याएं, रेलवे सुरक्षा बल, तथा बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी, अधिकारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार एवं उनकी वेलफेयर टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भावनगर रेलवे मंडल के मंडल कार्यालय एवं विभिन्न स्टेशनों पर योगाभ्यास का आयोजन

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में 21 जून, 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मंडल मुख्यालय सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रातः 06:00 बजे सामूहिक योग सत्रों का आयोजन किया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "योगा फॉर हेल्दी एजिंग" (Yoga for Healthy Ageing) अर्थात "स्वस्थ आयु के लिए योग" निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ, सक्रिय एवं संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देना है।

मंडल मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति, भावनगर के योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा

श्रीमती शालिनी वर्मा तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा के साथ मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान संबंधी अभ्यासों का प्रशिक्षण दिया गया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ताड़ासन, वज्रासन, पवनमुक्तासन, कपालभाति, अनुलोम-विलोम तथा ध्यान सहित विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी को नियमित योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश देते हुए कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वेलफेयर टीम द्वारा किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भावनगर मंडल के विभिन्न स्टेशनों जैसे भावनगर टर्मिनस, बोटाद, वेरावल, पोरबंदर, जूनागढ़, सिहोर, भाणवड, अमरेली, ढसा, लाठी, जेतलसर एवं गांधीग्राम सहित अन्य स्टेशनों पर भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें रेलवे कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

2020-26 में मोदी के चुनाव प्रचार पर 2586 करोड़ खर्च हुए: क्या इससे मीडिया पर सरकार का प्रभाव बढ़ा?

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

देश में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर खर्च होने वाले सार्वजनिक धन में हर साल उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त एक जवाब से पता चला है कि केंद्र सरकार ने 2020 से 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के विज्ञापनों पर लगभग 2586 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इस परियोजना पर कुल करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। 25,86,00,00,000 रुपये। और यह खर्च भारतीय करदाताओं के पैसे से किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने यह जानकारी देते हुए आरटीआई दाखिल की है।

गोखले ने 1 जून को एक आरटीआई आवेदन दायर कर मोदी के चुनाव अभियान के लिए केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, प्रिंट और होर्डिंग्स सहित सभी प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का खुलासा करने की मांग की थी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो ने 16 जून को आंकड़े जारी किए। इनमें 2020 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुसार व्यय का उल्लेख किया गया है। गोखले ने कहा कि हालांकि, जिन एजेंसियों को यह राशि प्राप्त हुई है, उनके नाम गुप्त रखे गए हैं। यह भारी आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि अकेले प्रिंट मीडिया में ही पार्टी ने 2025-26 में लगभग 338 करोड़ रुपये खर्च किए। जारी आंकड़ों के अनुसार, यह राशि पिछले वर्ष के 8316 करोड़ रुपये के व्यय से चार गुना अधिक है। कुल मिलाकर, 2020 से 2026 के बीच प्रिंट विज्ञापन पर व्यय 796 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है।

गोखले ने दावा किया कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकारी विज्ञापनों के जरिए मीडिया को नियंत्रित करते हैं। तो, जब मोदी और भाजपा के प्रचार पर 2586 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, तो क्या आपको आश्चर्य होता है कि हमारे मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है?

लगातार 5 साल तक खड़े रहना? दुलालगिरी महाराज के घोर तपस्या के दावे का वीडियो वायरल हो रहा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

दुललगिरी महाराज के नाम से जाने जाने वाले एक भिक्षु की कुछ तस्वीरें और वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि यह महाराज शिव की अत्यंत कठिन ध्यान साधना कर रहे हैं और उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया है।

सामान्यतया तपस्या और ध्यान बैठकर किया जाता है, लेकिन इस महाराज ने खड़े होकर तपस्या की है। वीडियो में दावा किया गया है कि यह महाराज कम से कम पांच वर्षों से खड़े हैं। वे खड़े-खड़े ही विश्राम करते हैं। इसीलिए उन्हें झूले पर अपने शरीर का अगला हिस्सा टिकाकर विश्राम करते हुए देखा जा सकता है।

लगातार खड़े रहने के कारण उनके घुटने सूज गए हैं। पैरों में रक्त संचार रुकने के कारण उनके पैर नीचे से काले पड़ रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि दुलालगिरी महाराज पांच साल नहीं बल्कि बारह साल से यह तपस्या कर रहे हैं। हालांकि, इन दावों की कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है।

मंदी, भुगतान संकट और बदलते बाजार पर चिंतन: एसएमए की बैठक में व्यापार बचाने की रणनीति पर हुआ मंथन

सूरत के कपड़ा व्यापार जगत में बदलती आर्थिक परिस्थितियों, घटती बिक्री और भुगतान संकट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सूरत मर्केन्टाइल एसोसिएशन (एसएमए) की 219वीं नियमित मासिक समस्या समाधान बैठक रविवार को माहेश्वरी भवन, सिटी लाइट में आयोजित की गई। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और उद्योग जगत के समक्ष खड़ी चुनौतियों पर चर्चा के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारियों, समाज के अग्रणियों और एसएमए पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक केवल शिकायतों और विवादों के निस्तारण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें सूरत के कपड़ा व्यापार के वर्तमान हालात, भविष्य की संभावनाओं और बदलते कारोबारी वातावरण के अनुरूप अपनाई जाने वाली नई रणनीतियों पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया गया।
एसएमए प्रमुख नरेंद्र साबू के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पंच पैनल और कोर कमेटी के सदस्यों ने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। कुल छह आवेदन पत्रों पर विचार किया गया, जिनमें से एक मामले का समाधान आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से तत्काल कर दिया गया। शेष मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए पंच पैनल और लीगल टीम को सौंप दिया गया, जो नियमानुसार उनकी जांच कर समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एसएमए का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को त्वरित और निष्पक्ष समाधान उपलब्ध कराना है ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया की लंबी जटिलताओं से बच सकें और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय वर्तमान व्यापारिक स्थिति रही, जिसने उपस्थित व्यापारियों की चिंता को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया। व्यापारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कारोबार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अप्रैल से जून के बीच बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना था कि बाजार में उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता कमजोर हुई है, जिसका सीधा असर कपड़ा कारोबार पर दिखाई दे रहा है। कई व्यापारियों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि दक्षिण भारत में शुरू होने वाले आडी सेल पीरियड के कारण आगामी महीनों में भी व्यापार पर दबाव बना रह सकता है।
बैठक में मौजूद व्यापारियों ने कहा कि बाजार की सबसे बड़ी समस्या

केवल कम बिक्री नहीं, बल्कि भुगतान में लगातार बढ़ती देरी भी है। दक्षिण भारत और अन्य राज्यों में माल भेजने के बाद भुगतान प्राप्त करने में कई बार चार से छह महीने का समय लग जाता है, जबकि कुछ मामलों में यह अवधि एक वर्ष तक भी पहुंच जाती है। इससे व्यापारियों की कार्यशील पूंजी पर गंभीर दबाव पड़ता है और नया कारोबार करना कठिन हो जाता है। व्यापारियों का कहना था कि लंबे समय तक फंसा हुआ पैसा उद्योग की गति को धीमा कर रहा है और छोटे तथा मध्यम स्तर के व्यापारियों के लिए स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है।
इस दौरान एसएमए पदाधिकारियों ने व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षित व्यापार नीति अपनाना समय की आवश्यकता है। संगठन की ओर से नकद कारोबार को प्राथमिकता देने की अपील की गई ताकि भुगतान संबंधी जोखिम कम किए जा सकें। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि व्यापारियों को अपने व्यवसाय को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखना है तो उन्हें उधारी आधारित कारोबार की सीमा तय करनी होगी और भुगतान की शर्तों को अधिक व्यवस्थित बनाना होगा।
बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि बदलते समय के साथ व्यापार की पारंपरिक पद्धतियों में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। केवल ऑफलाइन व्यापार पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं माना जा सकता। डिजिटल युग में ग्राहकों की खरीदारी की आदतें तेजी से बदल रही हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस संदर्भ में व्यापारियों को ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की दिशा में कदम बढ़ाने की सलाह दी गई। वक्ताओं ने कहा कि जो व्यापारी समय के साथ तकनीक को अपनाएंगे, वे भविष्य में अधिक प्रतिस्पर्धी और मजबूत स्थिति में रहेंगे।
बैठक में कपड़ा उद्योग की उत्पादन लागत से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। विशेष रूप से मिल प्रिंटिंग चार्ज में हाल ही में हुई वृद्धि को लेकर व्यापारियों ने चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि मशीन प्रिंटिंग की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे तैयार माल की कीमत पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके विपरीत डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक अपेक्षाकृत कम लागत, बेहतर गुणवत्ता और कम मात्रा में उत्पादन की सुविधा प्रदान कर रही है। कई व्यापारियों ने माना कि आने वाले समय में डिजिटल प्रिंटिंग कपड़ा उद्योग की दिशा बदल सकती है और व्यापारियों को इस तकनीक की ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
बैठक में सूरत के प्रोसेस हाउस संचालकों द्वारा 15 जून से लागू की गई नई दर वृद्धि का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। व्यापारियों ने इस निर्णय पर असहमति जताते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्पादन लागत बढ़ाना उद्योग के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनका कहना था कि जब बाजार पहले से ही मंदी और भुगतान संकट का सामना कर रहा है, तब अतिरिक्त आर्थिक बोझ व्यापार की स्थिति को और कमजोर करेगा। एसएमए ने प्रोसेस हाउस संचालकों से अपील की कि वे उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई दर वृद्धि को फिलहाल स्थगित करने पर विचार करें।
बैठक के दौरान यह भावना भी सामने आई कि सूरत का कपड़ा व्यापार अनेक उतार-चढ़ाव देखने के बावजूद पिछले पांच दशकों से देश के सबसे मजबूत व्यापारिक केंद्रों में शामिल रहा है। व्यापारियों का मानना है कि वर्तमान संकट भी स्थायी नहीं है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए सामूहिक प्रयास, अनुशासित व्यापार नीति और आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक होगा। कई वरिष्ठ व्यापारियों ने युवा उद्यमियों को सलाह दी कि वे केवल पारंपरिक व्यापार मॉडल पर निर्भर न रहें, बल्कि नए बाजारों, ऑनलाइन ग्राहकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की संभावनाओं का भी लाभ उठाएं।
बैठक के अंत में उपस्थित व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, सूरत का व्यापारिक समुदाय हमेशा अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और सामूहिक सहयोग के बल पर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलता रहा है। एसएमए ने भी आश्वासन दिया कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान, उद्योग के हितों की रक्षा और बेहतर व्यापारिक वातावरण तैयार करने के लिए संगठन निरंतर सक्रिय रहेगा।
स्वादिष्ट अल्पाहार के साथ संपन्न हुई इस बैठक में अशोक गोयल, महेश पाटोदिया, घनश्याम माहेश्वरी, मनोज अग्रवाल, अरविंद जैन, मुकेश अग्रवाल, राजेश गुरनानी, अशोक बाजारी, फूलचंद राठौड़, सुरेश मालपानी, राम बल्लभ चांडक, राजकुमार धनानिया, राजेंद्र कनोडिया, कविश मारू सहित अनेक वरिष्ठ व्यापारी और समाज के गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक ने स्पष्ट संकेत दिया कि सूरत का व्यापारिक समाज वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नए अवसरों की तलाश में आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

अब नहीं चलेगा 'नकली गांधी' का दौर, जनता ने परिवारवाद की राजनीति को किया खारिज: दिनेश प्रताप सिंह

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए कहा है कि देश की जनता अब परिवारवाद और प्रतीकात्मक राजनीति को भली-भांति समझ चुकी है और ऐसे "दौर का अंत" अब तय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अब वही राजनीति टिकेगी जो जमीन से जुड़ी होगी और जनता के वास्तविक मुद्दों पर काम करेगी, न कि विरासत या नाम के आधार पर आगे बढ़ेगी।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुलतानपुर के पर्यावरण पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर इसे पूरे वर्ष जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया योग अभियान आज वैश्विक पहचान बन चुका है और भारत की प्राचीन संस्कृति को दुनिया भर में सम्मान दिला रहा है। मंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सामाजिक अनुशासन का भी माध्यम है, जिसे हर नागरिक को अपनाना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में दिनेश प्रताप सिंह ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने हमेशा राजनीति को परिवार केंद्रित दृष्टिकोण से देखा है और जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाने की राजनीति करता है, जबकि सरकार विकास और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। मंत्री ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी लंबे समय तक करते रहे, वहां विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही और स्थानीय लोगों की समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं हो सका। विशेष रूप से अमेठी और रायबरेली का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में संसदीय प्रतिनिधित्व के बावजूद जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर अपेक्षित स्तर पर काम नहीं हुआ।
दिनेश प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियां बना रही है और विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता का जीवन आसान हुआ है।

सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा आरबीआई, ब्याज दरों पर फिलहाल नहीं दिख रहा बदलाव का संकेत

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में धीरे-धीरे स्थिरता लौटने और महंगाई के मोर्चे पर अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने फिलहाल सतर्कता की राह पर चलने के संकेत दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का गहराई से आकलन करना चाहता है। इसी वजह से आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को वर्तमान स्तर 5.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वित्तीय क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल 'वेट एंड वॉच' यानी प्रतीक्षा और निगरानी की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य के निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावी साबित हों।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज (बोफा) की हालिया रिपोर्ट में भी यही अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में वैश्विक स्तर पर कुछ सकारात्मक घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनसे आर्थिक अनिश्चितताओं में कमी आई है। विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को वैश्विक बाजारों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। इस समझौते के बाद ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी आशंकाएं कुछ हद तक कम हुई हैं और कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की संभावना भी घटी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जब वैश्विक तनाव कम होते हैं तो केंद्रीय बैंकों को आर्थिक संकेतकों के आधार पर निर्णय लेने के लिए अधिक स्पष्टता मिलती है। यही स्थिति इस समय भारत में भी दिखाई दे रही है। आरबीआई अब केवल अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय घरेलू आर्थिक आंकड़ों, महंगाई की स्थिति और विकास दर जैसे प्रमुख संकेतकों को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति तय करना चाहता है।
भारतीय रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से अपनी मौद्रिक नीति में संतुलित और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाए हुए है। जून में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था और नीति रुख को न्यूट्रल बनाए रखने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले को बाजार ने भी सकारात्मक रूप से लिया था, क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि और महंगाई दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक संकट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और भू-राजनीतिक तनावों ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं रहा। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, फिर भी केंद्रीय बैंक किसी भी संभावित जोखिम को नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार आगामी महीनों में मानसून की स्थिति आरबीआई के निर्णयों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल होगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून का सीधा असर खाद्य उत्पादन और खाद्य महंगाई पर पड़ता है। यदि मानसून सामान्य रहता है तो कृषि उत्पादन बेहतर होगा और खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव कम रहेगा। लेकिन यदि वर्षा में कमी या असमान वितरण की स्थिति बनी रहती है तो खाद्य महंगाई बढ़ सकती है, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती करना कठिन हो जाएगा।
इसी प्रकार कच्चे तेल की कीमतें भी आरबीआई की निगरानी में हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि का असर सीधे परिवहन लागत, उत्पादन लागत और अंततः महंगाई पर पड़ता है। फिलहाल वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के कारण तेल बाजार अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन केंद्रीय बैंक किसी भी संभावित जोखिम को लेकर सतर्क बना हुआ है।
बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। यह संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक वैश्विक और घरेलू चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास दर को लेकर थोड़ा सतर्क दृष्टिकोण अपना रहा है। दूसरी ओर महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत किया गया है, जो यह दर्शाता है कि मूल्य वृद्धि को लेकर चिंताएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।
मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने भी अपनी चर्चाओं में महंगाई और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को प्रमुख जोखिमों के रूप में रेखांकित किया है।

वर्ल्ड में पहली बार चलती ट्रेन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,डीआरएम वेद प्रकाश ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के साथ किया योगाभ्यास

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर 21 जून 2026 को मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के कुशल मार्गदर्शन में 12वाँ 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंडल के विभिन्न प्रमुख स्थलों के साथ-साथ चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में भी विशेष योग सत्र आयोजित किए गए। भारतीय रेलवे में पहली बार चलती ट्रेनों में यात्रियों को योग से जोड़ने की यह अभिनव पहल अहमदाबाद मंडल द्वारा की गई।
मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद मंडल द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। सबसे पहले हमने अपने सभी कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों को योग से जोड़ने का प्रयास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से हमारे विभिन्न केंद्रों तथा रेलवे संस्थानों में बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया।
दूसरी विशेष पहल के रूप में आज हमने वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को योग से जोड़ने की एक अनूठी पहल की है। इस अभियान के तहत ट्रेनों के 'पाइप्ड म्यूजिक' (ऑडियो सिस्टम) के माध्यम से योग गुरुओं के निर्देश प्रसारित किए गए तथा प्रत्येक कोच में उपस्थित वॉलंटियर्स ने यात्रियों

को अपनी सीट पर बैठे-बैठे 'सूक्ष्म योग' करने में सहयोग प्रदान किया। यात्रियों ने 10 से 20 मिनट तक गर्दन, हाथ, कलाई एवं कंधों के रोटेशन, ओम् के उच्चारण तथा ध्यान जैसे सरल योगाभ्यास किए। योग मन, वचन, कर्म और काया के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ एक स्वस्थ समाज, सशक्त राष्ट्र और बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग हमें संतुलन, अनुशासन और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सामुदायिक भवन, साबरमती में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में योगगुरु श्री अल्पेश त्रिवेदी एवं श्रीमती हंषा चाग ने रेल अधिकारियों, कर्मचारियों, आरपीएफ स्टाफ, स्काउट एवं गाइड तथा नागरिक सुरक्षा संगठन (सिविल डिफेंस) के सदस्यों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न आसनों, प्राणायाम एवं ध्यान संबंधी अभ्यासों का प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त ओल्ड रेलवे इंस्टीट्यूट-साबरमती, रेलवे इंस्टीट्यूट-कांकरिया, सामुदायिक भवन-गांधीधाम तथा सामुदायिक भवन-वीरमगाम में भी योग सत्र आयोजित किए गए।
चलती वंदे भारत ट्रेनों में विशेष योग सत्रइस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को और अधिक जनसुलभ एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में विशेष योग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें यात्रियों ने सीट पर बैठकर किए जाने वाले सरल योगाभ्यास एवं प्राणायाम का अभ्यास किया—

1. गाड़ी संख्या 20902 गांधीनगर कैपिटल – मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस
2. गाड़ी संख्या 12462 साबरमती – जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
3. गाड़ी संख्या 26964 असारवा – उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
4. गाड़ी संख्या 22925 अहमदाबाद – ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस

अहमदाबाद मंडल द्वारा पूर्व में भी अहमदाबाद, महेसाणा, पालनपुर तथा गांधीधाम सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर योग शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनमें रेल कर्मचारियों एवं यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 की थीम "Yoga for Healthy Ageing" के अनुरूप पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल स्वस्थ जीवनशैली और सामूहिक कल्याण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पश्चिम रेलवे अपने सभी सम्मानित रेल यात्रियों एवं रेल कर्मियों से अपील करता है कि वे योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ें तथा इस वैश्विक अभियान से जुड़ें।

योग से स्वस्थ समाज निर्माण का संकल्प, अग्रवाल समाज ट्रस्ट के शिविर में उमड़ा उत्साह

सूरत। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जहां देशभर में स्वास्थ्य, संतुलन और जागरूकता का संदेश दिया गया, वहीं सूरत में अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित विशेष योग शिविर ने समाज के लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। समाज ट्रस्ट के मालचंद सतनालीवाला हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला-पुरुषों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी आस्था और जागरूकता का परिचय दिया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और स्वास्थ्य चेतना से ओतप्रोत दिखाई दिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य केवल योग दिवस का औपचारिक आयोजन करना नहीं था, बल्कि समाज के लोगों को यह समझाना भी था कि आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं का प्रभावी समाधान योग के माध्यम से संभव है। बढ़ते तनाव, अनियमित दिनचर्या, शारीरिक निष्क्रियता और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के इस दौर में योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला बनकर उभरा है। इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए

अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने इस विशेष शिविर का आयोजन किया।
योग शिविर में प्रसिद्ध योगाचार्य पवन मित्तल ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। उन्होंने सरल और सहज तरीके से योग के महत्व को समझाते हुए बताया कि यदि व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकालता है तो वह न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत और संतुलित बन सकता है। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। योग केवल रोगों से मुक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और आत्मानुशासन विकसित करने का भी प्रभावी साधन है। योगाचार्य ने उपस्थित लोगों को यह भी बताया कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अधिकांश बीमारियां तनाव, चिंता और असंतुलित जीवनशैली के कारण बढ़ रही हैं। ऐसे में नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करता है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि योग को केवल एक दिन का कार्यक्रम न मानकर अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
शिविर में भाग लेने वाले लोगों ने विभिन्न योग क्रियाओं का उत्साहपूर्वक अभ्यास किया। सुबह के शांत वातावरण में जब सामूहिक रूप से प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया गया, तो पूरा परिसर सकारात्मक ऊर्जा से भर उठा। उपस्थित लोगों ने भी स्वीकार किया कि नियमित योग करने से स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार महसूस होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है।
अग्रवाल समाज ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर समाज के लोगों को नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि समाज भवन में प्रतिदिन सुबह 5:15 बजे से 7:30 बजे तक निःशुल्क योग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन कक्षाओं का उद्देश्य समाज के अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ना और उन्हें स्वस्थ जीवन की दिशा में प्रेरित करना है। ट्रस्ट का मानना है कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव रख सकता है। इसी सोच के साथ वर्षों से योग और स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान समाज ट्रस्ट की ओर से योगाचार्य पवन मित्तल का सम्मान भी किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश तोदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील गोयल, चेयरमैन श्रवण अग्रवाल, सचिव विनोद कनोडिया, कोषाध्यक्ष विनोद चिड़ावावाला तथा संरक्षक संजय जगनानी ने उन्हें सम्मानित करते हुए समाज के लिए उनके योगदान की सराहना की। पदाधिकारियों ने कहा कि योग प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े लोगों के प्रयासों से समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो रही है।

वडोदरा स्टेशन यार्ड रीमॉडलिंग प्रगति पर एकतानगर की कुछ वीकली ट्रेनें होगी डाइवर्टेड, कुछ ट्रेनों का वडोदरा की जगह विश्वामित्री, छायापुरी एवं बाजवा स्टेशनों पर हॉल्ट

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा स्टेशन पर व्यापक यार्ड रीमॉडलिंग एवं ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में प्लेटफार्म नंबर 5 एवं 6 की रेल लाइन पर पॉइंट एवं क्रॉसओवर को बैठाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे इन प्लेटफार्म पर 23 जून से ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। यात्रियों को न्यूनतम असुविधा को ध्यान में रखते तथा इंफ्रा के इस कार्य की जारी रखते हुए एकतानगर की कुछ वीकली ट्रेनें वडोदरा आने की बजाय डाइवर्टेड रुट डभोई - मियागाम कर्जन पर परिचालित होंगी। कुछ ट्रेनों को वडोदरा के स्थान पर शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़े विश्वामित्री, छायापुरी एवं बाजवा स्टेशनों

पर हॉल्ट दिया जायेगा। वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य परिचालन संरक्षा में वृद्धि, लाइन एवं प्लेटफॉर्म क्षमता का विस्तार, ट्रेन संचालन दक्षता में सुधार तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। 23 जून से 1 जुलाई ,2026 तक डाइवर्ट रुट डभोई - मियागाम कर्जन पर चलने वाली एवं विश्वामित्री, छायापुरी एवं बाजवा स्टेशनों पर हॉल्ट शिफ्ट होने वाली ट्रेनें निम्न है :

पालघर में शिवसेना ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र का शुभारंभ, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर

पालघर। आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पालघर में शिवसेना ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन शिवसेना उपनेता एवं ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र के अध्यक्ष अरुण जगताप के हाथों संपन्न हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम को व्यापक जनसमर्थन मिलता दिखाई दिया।
कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत और सम्मान समारोह के साथ हुई, जिसमें पालघर जिला ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र प्रमुख राजेंद्र आर. रांजणे ने पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल भेंट कर अरुण जगताप का अभिनंदन किया। इस अवसर पर संगठनात्मक एकता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया। उपस्थित नेताओं ने कहा कि इस प्रकार के केंद्र जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेंगे, जिससे लोगों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान संभव हो सकेगा।
इस उद्घाटन समारोह में नगरसेवक स्वप्निल बांद्रेकर, विशाल यादव, रवि शेट्टी, गणेश सेलार, पंकज श्रीवास्तव, सुभाष कनौजिया, विशाल पाटिल, दगडू जाधव, सुधीर वरणकर, रवि शिंदे, संतोष यादव और वेंकटेश भाई सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिवसेना संगठन की मजबूत उपस्थिति ने स्थानीय स्तर पर पार्टी की सक्रियता और जनसंपर्क को भी प्रदर्शित किया।
इसके साथ ही महिला मंडल की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। महिला कार्यकर्ताओं में नेना रांजणे, पद्मावती मुणुवर, सुजाता मीणा और संखे सहित अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने यह संदेश दिया

कि संगठन केवल पुरुष नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को समान रूप से महत्व दिया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि उद्घाटन के अवसर पर आयोजित चिकित्सा शिविर में 150 से अधिक नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में लोगों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह केंद्र केवल शिकायत निवारण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक कल्याण और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा।
उद्घाटन समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में आम नागरिक अनेक प्रकार की प्रशासनिक, उपभोक्ता और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो सकता है, जहां लोग अपनी समस्याएं सीधे तौर पर रख सकें और उनका त्वरित समाधान प्राप्त कर सकें। वक्ताओं ने यह भी कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई किसी भी जनसेवा प्रणाली की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और यह केंद्र इन्हीं मूल्यों पर कार्य करेगा।
नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके समाधान की प्रक्रिया को तेज करना है। इसके साथ ही लोगों को कानूनी और प्रशासनिक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान सही तरीके से प्राप्त कर सकें। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इस तरह के केंद्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान पहले की तुलना में अधिक तेजी से हो सकेगा। कई लोगों ने कहा कि छोटे-छोटे मुद्दों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन यदि एक ही स्थान पर शिकायत दर्ज कर उसका समाधान संभव हो सके तो यह एक बड़ी राहत होगी।
कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आभार व्यक्त किया।